

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2344

उत्तर देने की तारीख 16 मार्च, 2022

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के संविदा श्रमिकों को मजदूरी

2344. श्री एस.वेंकटेशन:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु टेलीकॉम सर्किल में अक्टूबर, 2020 से भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के संविदा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न किए जाने के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो संविदा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) बीएसएनएल कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा तमिलनाडु सर्किल को धनराशि के आवंटन का ब्यौरा क्या है और लंबित वेतन के दावों को निपटाने की समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या बीएसएनएल में विभिन्न कार्यों को आउटसोर्स किया गया और हजारों संविदा कर्मचारी अनुमोदित ठेकेदारों के माध्यम से काम कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार आउटसोर्स किए गए संविदा कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के लिए विभिन्न निर्देश और आदेश देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) सीधे संविदा श्रमिकों की नियुक्ति नहीं करता है। तथापि बीएसएनएल में हाउसकीपिंग, सुरक्षा, मरम्मत और अनुरक्षण जैसे विभिन्न गैर-प्रमुख कार्यकलाप अनुमोदित संविदाकारों के माध्यम से निष्पादित कराए जाते हैं जो संविदा श्रमिकों को नियुक्त करते हैं। बीएसएनएल अनुमोदित संविदाकारों से बिल प्राप्त होने पर निधियों की उपलब्धता के अनुसार संविदाकारों को भुगतान करता है संविदा श्रमिकों को संबंधित संविदाकारों द्वारा भुगतान किया जाता है। इस समय इस प्रकार के कार्यकलापों के लिए तमिलनाडु सर्किल में 447 संविदा श्रमिक कार्य कर रहे हैं।

बीएसएनएल कॉरपोरेट कार्यालय ने इस प्रकार के बिलों के भुगतान के लिए तमिलनाडु सर्किल को वर्ष 2021-22 के दौरान (फरवरी, 2022 तक) 82.33 करोड़ रूपए की निधि आवंटित की है। तमिलनाडु सर्किल में इस प्रकार के दिनांक 30.11.2021 तक प्राप्त सभी बिलों का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) बीएसएनएल प्रधान नियोक्ता के रूप में संविदा श्रमिकों के लिए ईपीएफ, ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के संबंध में निर्देशों/आदेशों का इन्हें एक निविदा शर्त के रूप में निविदा खंड में निर्धारित करके अनुपालन करता है।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2344
TO BE ANSWERED ON 16TH MARCH, 2022**

WAGES TO BSNL CONTRACT WORKERS

2344. SHRI S. VENKATESAN:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

- (a) whether the Government is aware about non payment of Wages to BSNL Contract workers from 01 October 2020 in Tamilnadu Telecom Circle and if so, the details of the action taken for payment of wages to Contract workers ;
- (b) the details of allotment of Funds from BSNL Corporate office to Tamilnadu Circle and the exact timeframe in which it is proposed to settle their pending wage claims;
- (c) whether various works in BSNL have been outsourced and thousands of contract workers are working through approved contractors and if so, the details thereof; and
- (d) whether the Government issues various instructions and orders for enforcement of Social Security Schemes like EPF, ESI to the outsourced, contract workers and if so, the details thereof?

ANSWER

**MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS
(SHRI DEVUSINH CHAUHAN)**

(a) to (c) Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) does not engage contract workers directly. However, various non-core activities like housekeeping, security, repair and maintenance in BSNL are performed through approved contractors, who in turn engage the contract workers. BSNL makes the payment to contractors on receipt of the bills from the concerned contractors as per availability of funds. The payment to the contract workers is made by the concerned contractors. At present 447 contract workers are working in Tamil Nadu circle for such activities.

BSNL Corporate Office has allotted fund amounting to Rs.82.33 Crores during 2021-22 (upto Feb 2022) to Tamil Nadu Circle for payment of such bills. In Tamil Nadu circle, all such bills received upto 30.11.2021 have been cleared.

(d) As a principal employer, BSNL follows the instructions/orders in respect of social security schemes such as EPF, ESI for the contract workers by framing the same in the tender clause as one of the tender conditions.
